फार्म फॉरवर्ड
वर्ष-1, अंक-6 : फरवरी 2025
जायका कृषि परियोजना-2 की मासिक ई-पत्रिका
Farm Forward
MONTHLY E-PAPER OF HPCDP (PHASE-II), JICA-ODA

प्राकृतिक खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था... पेज-3

अन्य पन्नों पर

जनवरी-फरवरी के कार्यः पेज-2
सोलन में 13 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूराः पेज-2
कैंसर रोधी भी है शिटाकेः पेज-2
पीला रतुआ रोगः पेज-2
संपादकीयः पेज-3
मोटे अनाजों की खेतीः पेज-3
नन्नैया परियोजना सौंपीः पेज-4
जवाली में नुक्कड़ नाटकः पेज-4
देहरा में नुक्कड़ सभाएंः पेज-4
ऊना में बाजार सर्वेक्षणः पेज-4
दुल्ला में कार्यशालाः पेज-4
फलतनाला में प्रशिक्षणः पेज-4
कोलनी का कार्य सौंपाः पेज-4
तडग्रा में सिंचाई सुविधाः पेज-4
जोगिन्द्रनगर में बैठकः पेज-4
एफआईएस कंसा खड्ड से गनेहर रोपा सौंपीः पेज-4

कृषि विभाग परियोजनाओं की 'एग्जिट पॉलिसी' पर काम करेगाः प्रो. चंद्र कुमार

100 सिंचाई उप-परियोजनाएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएंगी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विभाग को परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनके संचालन और प्रबंधन के लिए 'एग्जिट पॉलिसी' पर काम करने का निर्देश दिया और कृषि अनुसंधान संस्थानों को शुष्क भूमि कृषि पद्धतियों के मानकीकरण की संभावना तलाशने पर जोर दिया। प्रो. चंद्र कुमार 11 फरवरी को शिमला में जायका-ओडीए वित्त पोषित कृषि परियोजना के चरण-2 के कार्यान्वयन में लगे हिमाचल प्रदेश कृषि विकास सोसायटी की शासी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना के 1010 करोड़ रुपये के दूसरे चरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रो. कुमार ने कृषि विश्वविद्यालय से प्रदेश में कृषि उपज, विशेषकर सब्जियों, की उपलब्धता पर रणनीतिक अनुसंधान और योजना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। ये अनुसंधान इस दिशा में हो के जब पड़ोसी राज्यों से कृषि उपज की अपर्याप्त आपूर्ति हो, तब प्रदेश में ये उपलब्ध और किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छे मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने विदेशी सब्जियों के संकर बीजों के विकास पर अनुसंधान की आवश्यकता पर भी बल दिया।

परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने बैठक में परियोजना की प्रगति को दर्शाते हुए एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि जायका मिशन और कृषि विभाग 1,010 करोड़ रुपये की चरण-2 परियोजना पर सहमत हुए जिसमें से 807 करोड़ रुपये ऋण घटक हैं। वर्ष 2021 में शुरू की गई जायका कृषि परियोजना का चरण-2 हिमाचल प्रदेश के सभी

12 जिलों में लागू हुआ, जो 8,000 हेक्टेयर कमांद क्षेत्र को कवर करेगा, और इससे 25,000 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। बुनियादी ढांचे के विकास घटक के तहत 2029 तक परियोजना अवधि के नौ वर्षों में खर्च किए जाने वाले 330.70 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 296 सिंचाई उप-परियोजनाओं में से 100 इस साल मार्च के अंत तक लाभार्थियों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना शुरू कर देंगी। साथ ही, अगले वित्तीय वर्ष मार्च 2026 के अंत तक 100 और उप-परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। किसानों के समर्थन घटक पर परियोजना का परिव्यय 108.50 करोड़ रुपये है और अब तक 12.08 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मूल्य श्रृंखला और बाजार विकास पर लक्षित 63.30 करोड़ रुपये में से परियोजना ने 41.71 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राज्य के विपणन बोर्ड के 13 मार्केटिंग यार्ड के विकास के लिए परियोजना ने 31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने परियोजना के पहले चरण की प्रगति के बारे में जानकारी ली और उप-परियोजना क्षेत्रों के लिए 'एग्जिट-पॉलिसी' और सहायता के बारे में पूछा। डॉ. सुनील चौहान ने कृषि मंत्री को 'एग्जिट-पॉलिसी' बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि पिछले उप-परियोजना क्षेत्रों के किसानों को भी संगठित विपणन व्यवस्था और किसान उत्पादक संगठनों से जोड़ा जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. आर. पटेल ने राष्ट्रीय कृषि योजना और अन्य योजनाओं के तहत 'एग्जिट-पॉलिसी' के लिए राज्य को सहायता देने का आश्वासन दिया। परियोजना निदेशक डॉ. चौहान ने परियोजना के चरण-1 की उपलब्धियों का विवरण दिया। यह परियोजना फरवरी, 2011 में शुरू हुई और जून, 2021 में पूरी हुई। परियोजना के चरण-1 की लागत 321 करोड़ रुपये थी, जिसमें 210 सिंचाई उप-परियोजनाओं के निर्माण के लिए पांच कृषि जिलों में फसल विविधीकरण मॉडल स्थापित किये गये।

इस में 3712 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 4,671 हेक्टेयर कमांद क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं दी, जो 128 प्रतिशत रही। सकल वार्षिक औसत कृषि आय जो 2011 में प्रति हेक्टेयर 55,000 रुपये थी, और लक्ष्य 1.45 लाख रुपये करने का था, लेकिन 2021 में चरण-1 के दौरन प्रति हेक्टेयर सकल वार्षिक औसत कृषि आय बढ़ाकर 2.40 लाख रुपये हुई। इस तरह 165 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई।

कृषि मार्केटिंग के लिए एफपीओ बनाए जाएंगे : डॉ. सुनील चौहान

शिटाके मशरूम की मार्केटिंग अब होगी तेज; परियोजना के तीनों फार्मों में बीज उत्पादन होगा

हमीरपुर। जायका कृषि परियोजना के निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने अधिकारियों को कृषि मार्केटिंग के लिए कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) बनाने पर बल दिया। उन्होंने शिटाके मशरूम के उपयोग को लोकप्रिय बनाकर इसका उत्पादन और मार्केटिंग करवाने की जिम्मेदारी विपणन अधिकारियों को दी है।

परियोजना निदेशक डॉ. चौहान ने शिटाके मशरूम प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए कि इस विशेष खुम्ब (शिटाके) को उगाने के लिए अधिक से अधिक ब्लॉक्स का उत्पादन करें और यह मशरूम उगाने के लिए प्रशिक्षण दें। उन्होंने कहा कि परियोजना क्षेत्र में शिटाके मशरूम उगाने के लिए ब्लॉक्स का वितरण करें। उन्होंने बताया कि घरों में आसानी से शिटाके मशरूम को उगाया जा सकता है। इसके लिए पालमपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र से ब्लॉक्स मंगवाकर उन पर केवल पानी छिड़काकर ये मशरूम उगाए जा सकते हैं।

डॉ. सुनील चौहान ने परियोजना के बेरठी, भट्टू और करसोग फार्मों में बीज उत्पादन करने के निर्देश दिए और यह भी कहा कि बेरठी के फार्म को मॉडल फार्म के रूप में विकसित किया जाए।

डॉ. चौहान ने कहा कि घर-बगिया में प्राकृतिक खेती तकनीकी के प्रयोग पर भी बल देने के निर्देश दिए।

डॉ. चौहान 28 फरवरी शुक्रवार को परियोजना के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में तीनों परियोजना उप-निदेशक डॉ. डीडी शर्मा, डॉ. राजेश कुमार व डॉ. करतार सिंह, सोलन, हमीरपुर, मंडी व कांगड़ा (पालमपुर) प्रोजेक्ट जिला इकाइयों के प्रबंधक डॉ. राजेंद्र ठाकुर, डॉ. अनूप कतना, डॉ. एचआर वर्मा व डॉ. वाईपी कौशल, शिटाके खुम्ब प्रशिक्षण पालमपुर के प्रभारी अधिकारी डॉ. सपन ठाकुर, एसपीएमयू के विषय विशेषज्ञ डॉ. आशीष व डॉ. राकेश के अतिरिक्त परियोजना के विपणन अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में परियोजना प्रबंधन परामर्श इकाई से डॉ. आरके शर्मा व डॉ. आरएस ठाकुर भी उपस्थित थे।

डॉ. सुनील चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान परिवारों को खुशहाल बनाने की सोच को साकार बनाने के लिए जायका कृषि परियोजना-2 ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि परियोजना की मदद से किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मार्केटिंग नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया जा रहा है, साथ ही परियोजना क्षेत्र में 10 एफपीओ का गठन किया जा रहा है। अभी तक पपरोला, भट्टू व मटौर में तीन एफपीओ गठित किए जा चुके हैं।

डॉ. चौहान ने कहा कि परियोजना की कुल 296 सिंचाई उप-परियोजनाओं में से मार्च के अंत तक लगभग 100 सिंचाई उप-परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो जाएगा। उन्होंने परियोजना स्टाफ का आह्वान किया कि वे परियोजना क्षेत्र में फसल विविधीकरण को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाएं। उन्होंने कृषि उत्पादन और उत्पाद के विपणन के लिए परियोजना क्षेत्र के किसानों को अन्य बड़ी कृषि व्यापार संस्थाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

जायका कृषि फार्म बेरठी बनेगा मॉडल कृषि फार्म

सोलन। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना -2 के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने जिला परियोजना प्रबंधक इकाई, सोलन का दो दिवसीय दौरा किया जिसमें उन्होंने सोलन जिला में चल रही सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्यों का निरीक्षण के साथ-साथ लाभार्थी ध्यारी-ढल्ली-जदारी, वीडीएस बेरठी फार्म और सिंचाई परियोजना भलजानाला से वासनी का दौरा किया। इन सिंचाई परियोजना से जुड़े कृषक विकास संघ के प्रधानों से भी निर्माण कार्यों की चर्चा की गई ताकि निर्माण कार्यों में कोई भी कोताही न बरती जाये। इस सम्बन्ध में अधिकारियों /कर्मचारियों को समय पर काम को पूरा करने में जोर दिया गया इसके साथ ही परियोजना निदेशक के द्वारा लाभार्थी किसानों के लिए चलाई जा रही गतिविधियों का भी जायजा लिया।

इस दौरे के दौरान परियोजना के सम्बंधित पूरी टीम उनके साथ

किसानों व किसान संगठनों से परियोजना प्रगति के बारे में चर्चा की ताकि किसानों को और अधिक परियोजना की ओर से मदद दी जा सके। इसी सन्दर्भ में पहले दिन खंड परियोजना प्रबंधक इकाई, सोलन और नाहन के तहत सिंचाई परियोजना सभी परियोजना इंचार्जों को हिदायत भी दी गई ताकि सभी परियोजनाएं समय पर किसानों को सौंपी जा सके। दूसरे दिन परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन के सभी अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चल रहे कार्यों की समीक्षा की और सभी रही जिसमें उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कुमार और राकेश के साथ-साथ पीएमसी विशेषज्ञ डॉ. आर.एस. ठाकुर, परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन डॉ. राजेंदर ठाकुर और दोनों खंडों से सभी परियोजना अधिकारी मौजूद रहे।

शिटाके मशरूम की खेती का दिया प्रशिक्षण

पालमपुर। शिटाके खेती एवं प्रशिक्षण केंद्र, पालमपुर के द्वारा 13 से 20 फरवरी, 2025 तक शिटाके मशरूम की खेती में प्रशिक्षण करवाया जिसमें कुल 19 किसान प्रतिभागियों (एफआईएस बनी कूहल - 15, एफआईएस चौ कूहल -2 और एफआईएस भदुल कूहल-2) ने भाग लिया। यह 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शिटाके मशरूम की खेती कैसे की जाती है उसमें ध्यान देने वाली क्या-क्या बातें होती हैं और दो दिवसीय शिटाके मशरूम के प्रशिक्षण में प्रसंस्करण तकनीकों के बारे में सिखाया जाता है। इसका भंडारण और प्रसंस्करण कैसे किया जाता उस पर किसान प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण में शिटाके मशरूम की कटाई, प्रबंधन और किसानों को शिटाके कटाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। शिटाके प्रशिक्षकों के द्वारा शिटाके मशरूम की ग्रेडिंग, छंटाई और सुखाने के तरीकों, ताजा उपज की ग्रेडिंग और छंटाई के साथ-साथ इन मशरूम के विभिन्न भंडारण मानक और इसके लाभों को भी समझाया गया। समापन समारोह में योगेंद्र कौशल, जिला परियोजना प्रबंधक, पालमपुर ने किसानों को शिटाके मशरूम खेती में प्रशिक्षण लेने के लिए सभी किसानों को बधाई दी और सभी किसान प्रतिभागियों से आग्रह किया कि जो आपने इस केंद्र में सीखा है उसको अपने घर में जाकर इसकी खेती की शुरुआत करनी है ताकि इस प्रशिक्षण की सार्थकता बनी रहे, इसके साथ ही उन्होंने सभी किसानों से कहा कि आप व्यावसायिक रूप से शिटाके खेती करने के लिए आगे आयें जिससे आप सभी आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो।

जायका कृषि परियोजना ने पालमपुर में याटस कॉरपोरेशन, जापान के सहयोग से शिटाके मशरूम खेती प्रशिक्षण केंद्र (एस.सी.टी.सी) स्थापित किया गया है जिसमें 3.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। केंद्र में विशेष रूप से शिटाके मशरूम ब्लॉकों का उत्पादन, खेती प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधा है। एससीटीसी में शिटाके मशरूम के सुखाने की भी सुविधा है। इस केंद्र में शिटाके मशरूम की खेती 2023 से शुरू की जा चुकी है, जो पापुलर वृक्ष की लकड़ी के बुरादे व उसके छोटे टुकड़ों से बने ब्लॉकों पर हो रही है। खेती के लिए बीज (स्पॉन) खुम्ब अनुसंधान निदेशालय (आईसीएआर-डीएमआर), चंबाघाट, सोलन से लिया जा रहा था, जो अब इसी केंद्र में तैयार किया जाएगा। इस केंद्र में 1125 से अधिक किसानों को शिटाके मशरूम की खेती प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें इन्क्यूबेटेड शिटाके ब्लॉक भी दे रहा है ताकि किसान शिटाके मशरूम उत्पादन में परांगत हो सकें। इस समय इन्क्यूबेटेड शिटाके ब्लॉक का मुल्य केवल 200 रुपए रखा गया है। अब तक इस केंद्र ने 22 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके 263 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। 200 रुपए के एक ब्लाक से 6 महीने की फसल अवधि में औसतन 700 ग्राम से 800 ग्राम की फसल ली जा सकती है। किसान अच्छे लाभ के साथ ताजा शिटाके मशरूम को औसतन 800-900 रुपये प्रति किलो की दर से बेच सकते हैं। भारत 1200-4500 रुपये प्रति किलो की दर से शिटाके मशरूम (ताजा) का आयात कर रहा है। सुखाए गए शिटाके का औसतन मूल्य 350 रुपये प्रति 100 ग्राम है।

कैंसर-रोधी भी है शिटाके मशरूमः पेज-4 पर

'प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ाएं'

जायका कृषि परियोजना जिला हमीरपुर में हुए कार्यों पर एक नजर

हमीरपुर। जिला परियोजना प्रबंधक इकाई, हमीरपुर के अंतर्गत आने वाली तीनों खंड परियोजना प्रबंधन इकाइयों (हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना) ने जनवरी-फरवरी माह में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये जिसमें 569 किसानों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया इसके साथ ही फरवरी माह में एक दिवसीय 5 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये जिसमें 170 किसानों ने भाग लिया। अगर हम एमसी सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारी की बात करें तो बीपीएमयू बिलासपुर और बीपीएमयू ऊना ने 2 प्रशिक्षण एमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये गए जिसमें 42 किसानों सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। इन प्रशिक्षणों में सभी सदस्यों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। जिला परियोजना प्रबंधक इकाई, हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले 28 एमसी सदस्यों के एक समूह को तीन दिवसीय भ्रमण का आयोजन किया गया जिसमें कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और शिटाके मशरूम फार्म पालमपुर का दौरा प्रमुख था इसके साथ ही सभी किसानों को ढ्रंग में हिल स्प्राउट्स फार्म और विदेशी सब्जियों की खेती और वर्टिकल फार्मिंग में अपना नाम कमा चुकी भारती भूरिया के फार्म का भी किसानों का दौरा करवाया जिससे किसानों में कुछ करने का उत्साह बढ़ाया गया। इसके साथ ही एफपीओ पपरोला का भी दौरा किया जहां किसानों ने एफपीओ के संचालन और प्रभाव के बारे में

सीखा। जिला परियोजना प्रबंधक इकाई, हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले सभी बीपीएमयू ने 48 उप-परियोजना विकास योजनाएं तैयार कीं, जिनमें से अब तक 38 एसडीपी को केवीए द्वारा अनुमोदित किया गया है। कुल 54 सिंचाई परियोजना का निर्माण जिला परियोजना प्रबंधक इकाई, हमीरपुर के अंतर्गत होना है जिसमें से अब तक 40 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पीएमसी द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और 50 सिंचाई परियोजनाओं की डीपीआर को अब तक बना लिया है इसमें से 38 सिंचाई परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी करके 25 कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। अब तक 23 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जिसमें से एक सिंचाई परियोजना कोठी बटाला का निर्माण कार्य पूरा करके किसान विकास संघ को सौंप दिया है। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले सभी बीपीएमयू में किसानों को कृषि मंडियां कैसे काम करती हैं उनकी पूरी जानकारी शेप दृष्टिकोण के माध्यम से दी जा रही है। इसी के तहत 4 उप-परियोजनाओं में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य शेप के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त 6 उप-परियोजनाओं के किसानों को कृषि मंडियों में ले जाकर उनसे बाजार सर्वेक्षण भी करवाया गया। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य बाजार की मांग, मूल्य निर्धारण प्रवृत्तियों का आंकलन करना, किसानों को फसल चयन और विपणन रणनीतियों के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना था।

कोठी बटाला-ज्योरा सिंचाई उप-परियोजना को किया किसानों को समर्पित

उप परियोजना प्रवाह सिंचाई योजना कोठी बटाला-ज्योरा, ग्राम पंचायत रानी कोटला और धोबा, तहसील सदर जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के अंतर्गत कोठी बटाला और ज्योरा गांवों में स्थित है। इस सिंचाई परियोजना के लाभार्थी किसानों की संख्या 65 है और 15.98 हेक्टेयर का सकल कमांद क्षेत्र (जीसीए) और 11.90 हेक्टेयर का खेती योग्य कमांद क्षेत्र (सीसीए) शामिल है, इसकी निर्माण लागत लगभग 40 लाख है। इस सिंचाई योजना में 904.72 आरएमटी मुख्य चैनल (0.45 × 0.35) और कमांद क्षेत्र में बेहतर जल वितरण सुनिश्चित हो सके इसके लिए 912.55 (0.30 × 0.30) का निर्माण आरएमटी वितरण चैनल करवाया गया है, जिससे

कमांद क्षेत्र में बेहतर जल वितरण सुनिश्चित हो सके। इस सिंचाई परियोजना को आधिकारिक तौर पर परियोजना निदेशक की उपस्थिति में, इसके भविष्य के संचालन और रख-रखाव के लिए एफआईएस कोठी बटाला के किसान विकास संघ को सौंप दिया गया।

इस मौके पर परियोजना निदेशक के द्वारा उपस्थित किसानों को सम्बोधित करते हुए किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने तथा कृषि उत्पादकता और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

जायका कृषि परियोजना जिला सोलन में 13 सिंचाई उप-परियोजनाएं कृषक विकास संघों को सौंपी

सोलन। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन के अंतर्गत 3 खंड परियोजना प्रबंधन इकाइयों, सोलन, नाहन और रामपुर के द्वारा 58 सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं और लगभग 1343.17 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित की जाएंगी। अब तक 54 उप-परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा चुकी हैं, जिनमें से अब तक 50 डीपीआर स्वीकृत हो चुकी हैं। अब तक 47 सिंचाई परियोजनाओं की निविदायें जारी की जा चुकी है जिसमें से 40 उप-परियोजनाओं में निर्माण कार्य आवंटित किया गया है। फरवरी माह तक कुल 13 सिंचाई परियोजनाओं (सोलन-8 , नाहन-2 और रामपुर-3) का निर्माण कार्य पूरा करके इन सब कुल कमांद क्षेत्र लगभग 216.19 हैक्टर है इनको कृषक विकास संघों को सौंप दिया है। अब तक 47 सिंचाई परियोजनाओं (ऑनलाइन) का बेसलाइन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और साथ ही 39 सिंचाई परियोजनाओं की उप-परियोजना विकास योजना तैयार की गई है। लक्षित क्षेत्रों में वर्तमान कृषि पद्धतियों, चुनौतियों और अवसरों पर डेटा एकत्र किया जा रहा है, यह डेटा फसल विविधीकरण गतिविधियों, आजीविका गतिविधियों और विपणन योजनाओं सहित किसान सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों और योजना के लिए आधार के रूप में काम करेगा। फसल विविधीकरण के लाभों और तकनीकों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जा रहे हैं। वर्ष 2024 -25 के दौरान अभी तक जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन के सभी खंडों में 287 एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

आयोजन किया गया जिसमें 10 हजार से अधिक किसानों ने भाग लिया, जनवरी और फरवरी माह में कुल 57 एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाए गए जिसमें 1970 लाभार्थी किसानों ने भाग लिया।

17 और 18 फरवरी 2025 को बीपीएमयू सोलन और बीपीएमयू नाहन की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लाभार्थी किसानों के लिए प्रशिक्षण हॉल डीपीएमयू सोलन में जल प्रबंधन की तकनीकों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यूएचएफ नौणी से मौसमी सब्जियों के बीज

डीपीएमयू सोलन के तहत प्रदर्शन के उद्देश्य से किसानों को वितरित किए गए। इसके साथ ही पीएमसी ने डीपीएमयू इकाई के तहत पांच अलग-अलग उप-परियोजनाओं में निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी और डीपीआर की समीक्षा करने के लिए एक दौरा किया।

कैंसर-रोधी भी है शिटाके मशरूम

पालमपुर। शिटाके मशरूम जिसका तकनीकी लेंटिनुला एडोड्स है, जो मूल रूप से पूर्वी एशिया से है। शिटाके मशरूम का उपयोग विभिन्न एशियाई देशों में खाने के अतिरिक्त औषधीय रूप में भी किया गया है। इस मशरूम से निकाले गए लेंटीनन (बायोएक्टिव कंपाउंड) में कई एंटी-ट्यूमर यानी कैंसर रोधी गुण होने की पुष्टि हुई है और विभिन्न कैंसर उपचारों में औषधीय अनुप्रयोगों के साथ पाए जाने की सूचना है। यह कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड स्तर को सक्रिय रूप से प्रभावित करता है। शिटाके मशरूम कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। वे विटामिन डी और सारे बी विटामिनस जैसे कठिन से प्राप्त पौधे आधारित पोषक तत्वों से भरे हुए हैं। वे प्राकृतिक रूप से जिंक, सेलेनियम और तांबे, खनिजों से समृद्ध हैं जो स्वस्थ रक्त वाहिकाओं, हड्डियों और प्रतिरक्षा कार्यों का समर्थन करते हैं। प्राकृतिक लकड़ी के थैलों या ब्लॉक्स पर शिटाके की खेती चीन, ताइवान, जापान, कोरिया आदि देशों में की जाती थी। अब शिटाके मशरूम उत्पादन में हिमाचल प्रदेश भी जायका कृषि परियोजना के माध्यम से शामिल हो गया है। शिटाके मशरूम मूल रूप से पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक खाद्य कवक यानी फंगस है। इसका तकनीकी नाम लेंटिनुला एडोड्स है। यह मशरूम की ऐसी प्रजाति है, जो कैंसर और एड्स जैसे भयानक रोगों से लड़ता है। यह स्टमक और कोलोरेक्टल कैंसर में उपयोगी होती है। यह मशरूम कैंसर की दवाई लेटाइनन का मुख्य स्त्रोत है।

इस मशरूम का एक्सट्रैक्ट दवाई बनाने के लिए उपयोग में आता है। इस औषधीय मशरूम में एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग के गुणों के साथ-साथ विटामिन डी का भी काफी अच्छा स्त्रोत होता है। साथ ही, इसमें सेलेनियम और जिंक की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। जिसकी वजह से इस मशरूम का इस्तेमाल कई दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। इसके नियमित सेवन से इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाया जा

सकता है। इस औषधीय मशरूम में बीटा ग्लाइसीन और लिनॉलिक एसिड होता है, जो प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। शिटाके में सबसे अच्छी विशेषता वाले पॉलीसेकेराइड में से एक पानी में घुलनशील यौगिक है जिसे लेंटिनन के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से, क्लीनिकल अध्ययनों से पता चला है कि लेंटिनन कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। **1.** वजन कम करने में मदद करे: मशरूम के नियमित सेवन से आप बहुत ही कम समय में और सुरक्षित तरीके से अपना वजन कम कर सकते हैं। इसके लिए आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में उबाल कर खा सकते हैं। **2.** शुगर लेवल कम करे: मशरूम की अन्य प्रजातियों की तरह ही इस मशरूम में भी कार्बोहाइड्रेट्स की उच्च मात्रा होती है, जो बढ़े हुए ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं और यह डायबिटीज मरीजों के लिए यह सबसे अच्छा फूड हो सकता है। **3.** इम्युनिटी पावर बढ़ाए: सेलिनियम से भरपूर मशरूम इम्यून पॉवर को बढ़ाने के साथ-साथ सर्दी-खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं को से शरीर को बचाव करने में मदद करता है। **4.** दिल के रोग को रखे दूर: इसमें पाएं जाने वाले न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम दिल के रोगों का खतरा कम करते हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम 3 बार इसका सेवन जरूर करना चाहिए। **5.** पेट की समस्याओं से दिलाए राहत: कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा से भरपूर मशरूम का सेवन अपच, पेट दर्द, कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या को भी दूर करता है। रोगप्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, एचआईवी और एड्स में, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने, धमनियों को मजबूत बनाने के लिए, मधुमेह में, खुजली, सर्दी और बुखार में, प्रोस्टेट और ब्रैस्ट कैंसर के उपचार में, बढ़ती उम्र के निशान रोकने के लिए, हेपेटाइटिस-बी, हाई ब्लड प्रेशर, पेट का दर्द, दिल की देखभाल करने के लिए, हड्डियों की मजबूती बढ़ने के लिए।

गेहूं की फसल का पीला रतुआ रोग: लक्षण व उपचार

पीला रतुआ

हिमाचल प्रदेश में पीला रतुआ (येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट) गेहूं का प्रमुख रोग है। यह बीमारी प्रदेश में दिसम्बर के मध्य से लेकर फरवरी के पहले पखवाड़े तक आती है तथा इसके बाद फसल पर मार्च के अंत तक फैलती रहती है। रोग का प्रकोप अधिक ठण्ड और नमी वाले मौसम में ज्यादा होता है।

लक्षण

रोग के लक्षण पीले रंग की धारियों के रूप में पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जिनमें से पिसी हुई हल्दी जैसा पीला चूर्ण निकलता है जो रोग की गंभीर अवस्था में जमीन पर भी गिरा हुआ दिखाई देता है।

अधिक बीमारी वाले खेत में घूमने पर कपड़े भी पीले हो जाते हैं। यदि यह रोग कल्ले निकलने की अवस्था में या इससे पहले आ जाए तो फसल को भारी नुकसान होता है। पीली धारियां मुख्यत: पत्तियों पर ही पाई जाती हैं परन्तु रोग की व्यापक दशा में पत्तियों के आवरण, तनों एवं बालियों पर भी देखी जा सकती हैं।

रोग से प्रभावित पत्तियां शीघ्र ही सूख जाती हैं। इस रोग की वजह से सिकुड़े दाने पैदा होते हैं जिससे पैदावार में भारी कमी आती है। तापमान बढ़ने पर मार्च के अंत से पत्तियों की पीली धारियां काले रंग में बदल जाती हैं।

प्रबन्धन

1. हमेशा रोग रोधी किस्मों का ही प्रयोग करें।
2. क्षेत्र में अनुमोदित किस्मों की ही बुआई करें तथा ध्यान रखें कि दूसरे क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किस्मों को न उगाएं।
3. फसल पर रतुआ के लक्षण दिखते ही प्रॉपीकोनाजोल नामक कवकनाशी दवाई के 0.1 प्रतिशत घोल (30 मिली दवाई 30 लीटर पानी में प्रति कनाल) का छिड़काव करें। यदि रोग इस से पहले या बाद में दिखाई दे, तो भी दवाई का छिड़काव कर दें।
4. छिड़काव के लिए पानी की उचित मात्रा का प्रयोग करें। अधिक या कम मात्रा का प्रयोग करने से छिड़काव का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा।
5. छिड़काव दोपहर बाद करें।
6. यदि छिड़काव के बाद दो घण्टे के अन्दर बारिश आ जाती है तो मौसम ठीक होने पर दोबारा छिड़काव करें।

करनाल बंट

पीला रतुआ के अतिरिक्त प्रदेश में गेहूँ की बालियों में फूल आने के समय पर वातावरण में अधिक नमी या रूक-रूक कर बारिश होने पर, इस रोग का संक्रमण बढ़ जाता है। इसके कारण पौधे की कुछ बालियों में व एक बाली में कुछ ही दाने आंशिक रूप से काले चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं।

करनाल बंट के प्रबन्धन के लिए

प्रॉपीकोनाजोल 25 ई. सी. के एक कनाल के लिए 30 मि. ली. दवाई 30 लीटर पानी (1 मि. ली./1 लीटर पानी) में घोलकर, फसल में बूटिंग (बालियां निकलने से पहले की) अवस्था पर तथा पौधों में 50 प्रतिशत बालियां निकलने पर छिड़काव।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक फसल विविधीकरण

एक समृद्ध खेती समुदाय खाद्य सुरक्षा में सुधार, रोजगार अवसरों, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार करके ग्रामीण विकास को मजबूत बनाता है। यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए कृषि समुदाय की खुशहाली समग्र ग्रामीण समृद्धि के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। किसानों की खुशहाली के लिए जायका कृषि परियोजना जो सुविधाएं शामिल हैं, उनमें सिंचाई के अतिरिक्त और खेती तकनीकों की जानकारी उच्च गुणवत्ता के बीज, खादों और अन्य निवेशों की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इनसे फसल विविधीकरण के जरिए कृषि उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। कटाई, प्रसंस्करण और विपणन नेटवर्क की दोहराई जाने वाली प्रणालियों से किसान जुड़ रहे हैं। यह परियोजना किसानों को पारंपरिक, नकदी और उच्च मूल्य की फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। इस रणनीति से एक फसल पर निर्भरता व जोखिमों को कम करने में मदद करके किसानों की आय बढ़ रही है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की नीति को जमीन पर उतारने की सोच रखते हैं। जायका कृषि परियोजना, फसल विविधीकरण के प्रतिकृति मॉडल के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे कर मुख्यमंत्री इस नीति पर अमल कर रहे हैं।

जायका कृषि परियोजना के कार्यक्रमों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़ रहे हैं।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार: सिंचाई और फार्म एक्सेस रोड़ से ग्रामीण बुनियादी

ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है।

रोजगार सृजन: एक संपन्न कृषि क्षेत्र गांव में प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण और खुदरा जैसे संबंधित क्षेत्रों में नौकरी के अवसर बढ़ा रहा है जिससे बड़ी ग्रामीण आबादी को आजीविका के संसाधन मिल रहे हैं।

सामाजिक विकास: किसान एवं स्वयं सहायता समूहों के गठन और समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षित करके किसानों और किसान महिलाओं को सामाजिक तौर पर जोड़ा जा रहा है। इस तरह समृद्ध किसान परिवार अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा दे सकेंगे, जिससे समग्र सामाजिक प्रगति में सुधार हो सकता है.

पर्यावरणीय स्थिरता: समृद्ध किसानों को पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की उनकी क्षमता के कारण स्थायी खेती प्रथाओं को अपनाने की अधिक संभावना हो सकती है।

खाद्य सुरक्षा: पोषक घर-बगिया से परिवार के संतुलित पोषण को बनाया जा रहा है, फसलों के विविधीकरण से भी अनाज, सब्जियों और दालों आदि की खेती को बढ़ावा देकर किसानों को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और तो और जब किसान समृद्ध होंगे तो यह बेहतर कृषि प्रणालियों में निवेश कर अपने क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा में पूरा योगदान दे सकते हैं।

आर्थिक विकास: कृषि आय में वृद्धि से गांव के भीतर कृषि उत्पादन, उत्पादों सेवाओं का विस्तार हो रहा है, जिससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह से समृद्ध किसान परिवार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई लहर पैदा कर रहे हैं।

डॉ. सुनील चौहान
परियोजना निदेशक
एवं प्रधान सम्पादक

प्राकृतिक खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर दिया जा रहा बल: मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में किसानों को सशक्त और ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि खेती की लागत को कम करने किसानों की आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जहां मानव और पर्यावरण को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाया जा रहा है, वहीं खेती की लागत कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसान-बागवान विविध फसलों व फलों को प्राकृतिक खेती से उगा रहे हैं। प्रदेश की 3,592 पंचायतों में एक लाख 98 हजार किसान 35 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती से विविध फसलें उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती पर विशेष बल देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से कृषि की लागत में औसतन 36 फीसदी की कमी आई है और उत्पादों के औसतन 8 फीसदी अधिक दाम मिले हैं। प्राकृतिक खेती कर रहे 75 फीसदी किसान-बागवान फसल विविधिकरण की ओर अग्रसर हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी दस वर्षों में राज्य को 'समृद्ध और आत्मनिर्भर' बनाने के लिए आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। हमारी सरकार 'समृद्ध किसान समृद्ध हिमाचल' के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तीसरे चरण के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना की शुरूआत की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश

सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने के साथ पूरे देश में गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक 40 और 30 रुपये का समर्थन मूल्य तय किया है। इसके तहत प्रत्येक प्राकृतिक खेती करने वाले किसान परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदा जाएगा। हाल ही में कृषि विभाग ने प्रदेश के 1,508 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद कर 'हिम-भोग हिम प्राकृतिक' मक्की आटा बाजार में उतारने के साथ प्राकृतिक उत्पादों के लिए 'हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना' की भी शुरूआत की है। ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में सात जिलों में बागवानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,292 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है जहां गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र से 20,000 से अधिक डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, कांगड़ा जिले के ढगवार में पूरी तरह से स्वचालित दूध और दूध उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रख दी गई है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। कुल्लू, नाहन और नालागढ़ में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे जबकि ऊना और हमीरपुर में आधुनिक मिल्क चिलिंग प्लांट की योजना बनाई जा रही है। मिल्कफेड वर्तमान में प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध खरीद रहा है और एक अग्रणी पहल के रूप में ऊना जिले में बकरी का दूध 70 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये की 'हिम गंगा' योजना शुरू की गई है। पिछले दो वर्षों में 26,000 बीपीएल किसानों को मवेशियों के चारे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिली है जिससे डेयरी क्षेत्र को महत्वपूर्ण मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरूआत की गई है। मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत बकाया भुगतानों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 12 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि बाड़बंदी के लिए 70 प्रतिशत तक तथा अनाज, दलहन, तिलहन और चारा फसलों के लिए बीज पर 50 प्रतिशत और आलू, अदरक और हल्दी के बीज के लिए 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में जायका योजना के तहत जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर 96.15 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट: हल्दी निर्यात को लेकर हुई विशेष चर्चा

ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू से भेंट की इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूके की डिप्टी हाई कमीशनर कैरोलिन रौवेट और यूके सरकार के राजनीतिक, प्रेस और परियोजना सलाहकार राजेंद्र एस नागरोटी ने किया। इस बैठक में यूके-हिमाचल प्रदेश के संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश से यूके को हल्दी निर्यात को लेकर विशेष चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री ने गहरी रुचि दिखाई और इस व्यापारिक अवसर को सुलभ बनाने पर बल दिया। कैरोलिन रौवेट ने हिमाचल प्रदेश और यूके के निवेशों के बारे में बताया और कहा कि बैठक के दौरान कुछ में एक कृषि उद्योग और राज्य में भारतीय संचालित स्कॉटिश डिस्टिलरी की स्थापना के बारे में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैठक यूके-हिमाचल के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग और आदान-प्रदान के नए अवसर सृजित होंगे।

हिमाचल प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती

वर्तमान में प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र के किसानों द्वारा अपने स्वंय के उपयोग के लिए पोषक अनाजों (मिलेटस) को परम्परागत रूप में उगाया जाता है। प्रदेश में इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए व किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक तकनीकी आदान व बाजार लिंकेज प्रदान करना आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पोषक अनाजों जैसे कोदा, कंगणी, सांवां, चौलाई, कुटकी इत्यादि की व्यापक खेती की जाती है। इनकी यह विशेषता है कि यह कम उपजाऊ भूमि के ढलानदार खेतों में भी बिना किसी खाद या उर्वरक और बारानी परिस्थितियों में पैदा होने की क्षमता रखते हैं।

यह अनाज इम्युनिटी बूस्टर का काम करते है। इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फाइबर, विटामिन बी-6 मौजूद होते हैं। मधूमेह के रोग में भी यह फायदेमंद होते हैं। इसके अतिरिक्त यह अनाज ग्लूटिन मुक्त होते हैं, इसलिए गेहूं से एलर्जी की समस्या की दशा में इनका उपयोग फायदेमंद होता हैं।

पोषक अनाजों (मिलेटस) का विवरण

प्रचलित नाम रागी (फिंगर मिलेट)

स्थानीय नाम रागी, कोदा, कोदरा, मण्डुआ, मण्डल

किस्में हिमाचल प्रदेश में सामान्यत: स्थानीय किस्मों की ही बिजाई की जाती है परन्तु वी. एल-117, वी. एल. 204 और वी. एल. -115 किस्मों की सिफारिश की जाती है जो शीघ्र तैयार होने व अधिक उपज देने वाली किस्में हैं।

बीज की दर (किलोग्राम /बीघा) 1.5
उपज (किलोग्राम/बीघा) अनाज/भूंसा/घास अनाज:120

प्रचलित नाम सांवां (बरनयाड़ मिलेट) **किस्में** स्थानीय किस्में

स्थानीय नाम सौंक, सांवां, जिंगोरा

बीज की दर (किलोग्राम /बीघा) 0.7-0.8
उपज (किलोग्राम/बीघा) अनाज/भूंसा/घास अनाज: 96-120 भूंसा/घास: 160-200

प्रचलित नाम कंगणी (फोक्सटेल मिलेट) **किस्में** स्थानीय किस्मों की ही बिजाई की जाती है। कंगनी में एच के सी-8 और एच के सी-9 किस्मों को उगाया जा सकता है।

स्थानीय नाम कंगणी, कौंणी

बीज की दर (किलोग्राम /बीघा) 0.7-0.8
उपज (किलोग्राम/बीघा) अनाज/भूंसा/घास अनाज: 120-144 भूंसा/घास: 160-320

प्रचलित नाम कुटकी (लिटल मिलेट) **किस्में** स्थानीय किस्में

स्थानीय नाम कुटकी

बीज की दर (किलोग्राम /बीघा) 0.7-0.8
उपज (किलोग्राम/बीघा) अनाज/भूंसा/घास अनाज: 96-120 भूंसा/घास: 160-200

प्रचलित नाम कोदो मिलेट **किस्में** स्थानीय किस्में

स्थानीय नाम कोदो

बीज की दर (किलोग्राम /बीघा) 0.8-1.0
उपज (किलोग्राम/बीघा) अनाज/भूंसा/घास अनाज: 120-145 भूंसा/घास: 240-320

भूमि व इसकी तैयारी: पोषक अनाजों को विभिन्न प्रकार की भूमियों, दोमट से कम उपजाऊ में उगाया जा सकता है। 2-3 बार हल चलाकर खेत को तैयार किया जाता है। 24 क्विंटल गली-सड़ी गोबर की खाद या 20 कि.ग्रा. घन जीवामृत प्रति बीला बिजाई से पहले भूमि में मिला दें। पोषक अनाजों को प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार करने की सिफारिश की जाती है, ताकि इसकी गुणवता बनी रहे।

बिजाई का समय: मई का पहला सप्ताह पोषक अनाजों की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। परन्तु मौसम के अनुसार इन्हें मई के तीसरे सप्ताह तक बीजा जा सकता है। निचले क्षेत्रों तथा कम उपजाऊ भूमी में, इनकी बीजाई जून के तीसरे सप्ताह तक की जा सकती है।

बिजाई का ढंग:

(1) केरा विधि द्वारा 25 सैं.मी. के अन्तर की कतारों में पोषक अनाजों की बिजाई करें। अंकुरण के तीन सप्ताह बाद आवश्यकता से अधिक पौधों को निकाल दें ताकि पौधों के बीच में 10 सैं.मी. का अन्तर रह जाए।

(2) रोपाई विधि से इनकी बीजाई करने की सिफारिश की जाती है। रोपाई विधि से लगाई गई फसल में निराई व गुड़ाई करना आसान रहता है व पौधों व कतारों का अन्तर भी सही रहता है। इससे पैदावार अच्छी होती है।

बीज का उपचार: बीजाई से 24 घण्टे पहले बीजामृत से बीज का उपचार करें। उपचार के बाद, छाया में सूखा लें और बीजाई करें।

निराई - गुड़ाई: दो बार निराई-गुडाई करने से खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। पहली निराई-गुड़ाई अधिक पौधों को निकालते समय तथा दूसरी निराई-गुड़ाई मध्य जुलाई में करें।

सिंचाई: पोषक अनाजों में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है। बिजाई के समय मिट्टी में उपयुक्त नमी होनी चाहिये, ताकि अंकुरण अच्छा हो। रोपाई विधि द्वारा लगाई गई फसल में रोपाई के तुरन्त बाद ही सिंचाई करें। इसके अतिरिक्त यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो आवश्यकता के अनुसार एक या दो बार सिंचाई करें।

कटाई व गहाई: अक्तूबर के पहले सप्ताह में फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पक्की बालियों को काटकर अच्छी तरह से सुखा लें। सूखी बालियों को डंडों से पीटकर या फसल पर बैलों को चलाकर दानों को निकाला जाता है और साफ कर लिया जाता है।

चौलाई:

स्थानीय नाम: चौलाई, राजगीरी, रामदाना, सलियारा चौलाई (साग) या स्यूलि (रामदाना) अधिक पौष्टिक फसल है जिसे कम पानी व कम

प्रचलित नाम चीणा (प्रोसो मिलेट) **किस्में** स्थानीय किस्में

स्थानीय नाम चीणा

बीज की दर (किलोग्राम /बीघा) 0.8-0.9
उपज (किलोग्राम/बीघा) अनाज/भूंसा/घास अनाज: 160-240 भूंसा/घास: 400-480

उर्वरक की मात्रा से मध्यवर्ती व ऊंचे क्षेत्रों की ढलानदार भूमियों में उगाया जा सकता है। स्यूलि को भून कर दूध या दहीं में मिलाकर धार्मिक उपवासों के अवसरों पर प्रयोग में लाया जाता है। इसके लगातार प्रयोग करने से भोजन को पौष्टिक बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में सामान्यत: स्थानीय किस्मों की ही बिजाई की जाती है परन्तु अन्नपूर्ण, दुर्गा, पीआरए-9401 तथा सवरना जैसी उन्नत किस्मों के लगाने से अधिक उपज प्राप्त हो सकती है।

भूमि: इसे सभी प्रकार की भूमियों (उदासीन से क्षारीय) में उगाया जाता है और ढलानदार खेतों में पानी का रिसाव अच्छा होना चाहिए। भूमि को हल चलाकर तैयार करना चाहिए और 4 क्विंटल प्रति बीघा देसी खाद या 20 किलोग्राम घन जीवामृत डालना चाहिए।

बिजाई का समय: इसकी बिजाई जून के आरम्भ से जून के अन्त तक करनी चाहिए। परन्तु यह क्षेत्र की ऊंचाई व मौसम पर निर्भर करती है। निचले क्षेत्र में इसे मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बीज देना चाहिए परन्तु मानसून आने से 15-20 दिन पहले बिजाई कर देनी चाहिए अन्यथा पौधों की बढ़ौतरी ठीक नहीं हो पाती है।

बीज की मात्रा एवं बिजाई: 2-2.5 कि.ग्रा. बीज प्रति हैक्टेयर पर्याप्त होता है। बिजाई केरा विधि से 2 सै.मी. गहराई में 50 सै.मी. के अन्तर की कतारों में करनी चाहिए और पौधों के बीच 25 सै.मी. का अन्तर होना चाहिए।

निराई-गुडाई: अधिक उपज के लिए दो बार निराई गुडाई करें।

कटाई: फसल को भूमि के साथ काट लेना चाहिए और खेत में कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। डंडों से सूखे फल वाले भाग को पीटा जाता है और फिर दानों को सुखाकर साफ कर लिया जाता है।

उपज: 64-80 किलोग्राम/बीघा

सौजन्य : कृषि विभाग, हि.प्र.

मोटे अनाजों में पोषक तत्व

प्रति 100 ग्राम

अनाज	प्रोटीन (ग्रा.)	फाइबर (ग्रा.)	खनिज (ग्रा.)	आयरन (मि. ग्रा.)	कैल्शियम (मि. ग्रा.)
बाजरा	10.6	1.3	2.3	16.9	38
कोदा	7.3	3.6	2.7	3.9	344
कांगणी	12.3	8	3.3	2.8	31
चीणा	12.5	2.2	1.9	0.8	14
कोदो	8.3	9	2.6	0.5	27
कुटकी	7.7	7.6	1.5	9.3	17
सांवां	11.2	10.1	4.4	15.2	11

सौजन्य : भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान

'प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ाएं'

जवाली में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को किया जागरूक

जवाली, 24 फरवरी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत खंड परियोजना प्रबंधक इकाई, जवाली द्वारा सोमवार को बहाव सिंचाई योजना, सम्केहड़ (निर्वाचन क्षेत्र - जवाली) में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को परियोजना की विभिन्न गतिविधियों, उसके लाभों तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना था। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को फसल विविधीकरण, जल प्रबंधन, सिंचाई प्रणालियों के कुशल उपयोग, प्राकृतिक खेती और परियोजना से जुड़ी अन्य पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को सदस्यता शुल्क, परियोजना के रख-रखाव एवं संचालन संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में परियोजना टीम और किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। परियोजना प्रबंधन इकाई ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि किसानों को नई तकनीकों, योजनाओं और कृषि विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समय-समय पर मिलती रहें।

नन्नैया के किसानों को सौंपी सिंचाई परियोजना

पालमपुर। प्रदेश में किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने एवं कृषि क्षेत्र में विकास को गति देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के तहत विभिन्न विकास कार्यों का संचालन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में, ग्राम पंचायत कन्द्रेहर के अंतर्गत निर्मित सिंचाई परियोजना नन्नैया का विधिवत हस्तांतरण कृषक विकास संघ एवं स्थानीय किसानों को किया गया। इस सिंचाई परियोजना से लगभग 24.6 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जिससे क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना के निर्माण पर कुल 31.50 लाख रुपये की लागत आई और इस परियोजना से 268 किसान लाभान्वित होंगे।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. योगिंदर पॉल कौशल ने ग्राम पंचायत प्रधान नरेश कुमार का स्वागत किया और किसानों को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में विषयवाद विशेषज्ञ डॉ. रजनीश शर्मा और खंड परियोजना अधिकारी डॉ. अंकिता शर्मा ने परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी किसानों को दी।

इस अवसर पर कृषक विकास संघ नन्नैया की प्रधान रीना देवी ने कृषि विभाग एवं जायका परियोजना दल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सिंचाई परियोजना क्षेत्र के किसानों को सब्जी उत्पादन एवं कृषि से आय वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे इस सुविधा का अधिकतम उपयोग कर आधुनिक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिससे सतत् कृषि विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह परियोजना प्रदेश सरकार की किसान-कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय किसानों को जल संकट से मुक्ति मिलेगी और वे कृषि में विविधीकरण कर अपनी आजीविका को और सशक्त बना सकेंगे।

नुक्कड़ सभाओं से किसानों को मिल रही नई जानकारी

देहरा। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग एवं हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना - 2 के संयुक्त प्रयासों से किसानों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से परिचित कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से किसानों को न केवल खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है, बल्कि मनोरंजक तरीकों से पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नकदी फसलों की ओर रुझान बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे।

इसी क्रम में खंड परियोजना प्रबंधक देहरा के अंतर्गत बहाव सिंचाई योजना तकीपुर, दवाड़ और कनोल में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में किसानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विशेषज्ञों से उपयोगी जानकारी प्राप्त की। विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत बीज, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, एकीकृत कीट नियंत्रण और सरकारी कृषि योजनाओं के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नकदी फसलों को अपनाने और कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष जोर दिया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। किसानों ने इस आयोजन को बेहद उपयोगी बताया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। इस पहल से भविष्य में क्षेत्र के किसान आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

परियोजना इकाई, ऊना ने करवाया बाजार सर्वेक्षण

ऊना। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत खंड परियोजना प्रबंधन इकाई ऊना द्वारा सिंचाई परियोजना मंधोली के लाभार्थी किसानों से शैप अप्रोच के माध्यम से सब-मार्केट यार्ड टकराला में बाजार सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें उप परियोजना मंधोली के 8 किसानों ने भाग लिया।

कमीशन एजेंटों द्वारा किसानों को बाजार के रुझान के बारे में समझाया गया और किसानों को कब किस फसल को उगाने से बाजार में अच्छा मूल्य मिल सकता है इस बात पर भी किसानों के साथ विस्तार में चर्चा हुई। इसके साथ ही किसानों का स्थानीय बाजार कलरुही में भी सर्वेक्षण करवाया। बाजार के रुझान की जानकारी देने के लिए किसानों ने जायका विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद किया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि वे बाजार उन्मुख खेती करके अपनी आय को दोगुना करेंगे।

तड़ग्रा गांव के किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा

चम्बा। अब तड़ग्रा गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के तहत तड़ग्रा गांव में 24 लाख रुपये की लागत से कूहल निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना का निर्माण कार्य आठ महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। इस कूहल के निर्माण से करीब 12 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा, जिससे 86 किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक सिंचाई के लिए बारिश और अन्य अस्थायी स्रोतों पर निर्भर रहने वाले किसानों को अब नियमित सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित होगी। इससे उनकी फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और जल संकट की समस्या से राहत मिलेगी। खंड परियोजना अधिकारियों के द्वारा कूहल निर्माण के लिए ठेकेदार को कार्य सौंप दिया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस परियोजना से न केवल किसानों की खेती सुचारू रूप से चलेगी, बल्कि फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे वे पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नकदी फसलों की ओर रुख कर सकेंगे। कूहल निर्माण से सिंचाई की सुविधा मिलने के बाद किसानों की फसल उत्पादन लागत में कमी आएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने से वे नई कृषि तकनीकों को अपनाने में भी सक्षम होंगे।

सिंचाई परियोजना क्षेत्र दुल्ला में हुई कार्यशाला

चम्बा। चम्बा जिले के अधिकांश किसान रबी सीजन में गेहूं, जौ, सरसों, चना और मटर जैसी फसलों की खेती करते हैं। इन फसलों को विभिन्न प्रकार के कीट, बीमारियों और खरपतवार से नुकसान पहुंचता है, जिससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए खंड परियोजना के तहत सिंचाई परियोजना दुल्ला में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां किसानों को कीट एवं खरपतवार नियंत्रण के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान गेहूं और गोभी की फसल में कीट एवं खरपतवार नियंत्रण के महत्व पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि गेहूं की उच्च पैदावार सुनिश्चित करने के लिए खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि अनियंत्रित खरपतवार पौधों के विकास को बाधित करते हैं और जिससे उत्पादन भी कम होता है। इस अवसर पर लाभार्थी किसानों को खरपतवार और कीट नियंत्रण हेतु आवश्यक दवाइयां भी वितरित की गईं।

कार्यशाला के बाद कृषि विशेषज्ञों ने जायका वेजिटेबल गार्डन के अंतर्गत किसानों द्वारा उगाई गई गोभी की फसल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसानों को गोभी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि समय पर कीटनाशक एवं जैविक उपचार अपनाने से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों ने जानकारी को अत्यंत उपयोगी बताया और कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं से उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सहायता मिलती है।

कृषि विभाग एवं जायका परियोजना के तहत ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से किसानों को फसलों के बेहतर प्रबंधन, उन्नत तकनीकों और कृषि विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

जोगिन्दरनगर में हितधारकों और किसानों के बीच हुई बैठक

सरकाघाट। दिनांक 22.02.2025 को खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, सरकाघाट द्वारा जोगिन्दरनगर उपमण्डल के सैटेलाइट कार्यालय चौंतड़ा में एक शिविर का आयोजन किया गया इसमें 30 लाभार्थियों ने भाग लिया जिसमें स्थानीय बाजार हितधारक फोरम (कृषि इनपुट आपूर्तिकर्ता, खरीदार, फसल निर्यातक, वित्तीय संस्थान, गैर सरकारी संगठन आदि) की और से प्रतिनिधियों ने किसानों को एग्रीकल्चर सप्लायर, इनपुट, वित्त के बारे में जानकारी दी। विभिन्न कवकनाशकों और कीटनाशकों, हस्तनिर्मित जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को प्रदर्शनी प्रस्तुत की प्रोजेक्ट की तरफ से डॉ. अश्वनी कुमार बीपीएम सरकाघाट, ऋचा बहमन एई, निशांत पराशर एईओ ने परियोजना में होने वाले कार्य जैसे कि शेप के उद्देश्य, बाजार रणनीतियां उच्च मूल्य और मांग वाली फसलों की खेती, सब्जियों की फसलों में क्षेत्र का विस्तार, सब्जी की फसलों खेती की पद्धतियां, लिंकेज चैनल बनाकर किसानों को फसलों की उच्च दर प्राप्त करने के लिए जागरूक किया।

फलतनाला में दिया किसानों को फसलों की उन्नत खेती का प्रशिक्षण

कुल्लू। 22 फरवरी, 2025 को खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई से कृषि अधिकारी संजय कुमार ने जल बहाव सिंचाई परियोजना फलतनालाह में शेप के तहतलाभार्थियों को एक दिवसीय क्षेत्र प्रशिक्षण दिया गया। इस क्षेत्र प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य में लाभार्थियों को फसलों को उगाने तथा फसलों में आने वाली बीमारियों के बारे में अवगत करवाया तथा बीमारियों के निवारण के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा की। लाभार्थियों ने फसलों को उगाने से लेकर फसलों कि कटाई तक के समय के बीच आने वाली चुनोतियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की ।

जल बहाव सिंचाई योजना कोलनी का कार्य ठेकेदार को सौंपा

सरकाघाट। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत खंड परियोजना प्रबंधन इकाई सरकाघाट की ओर से जल बहाव सिंचाई योजना कोलनी के निर्माण कार्य के लिए उप-परियोजना को दिनांक 21 फरवरी, 2025 को ठेकेदार को सौंपा। इस उप-परियोजना के निर्माण के लिए रुपए 44,06,534/- आबंटित किये गए हैं, इस उप-परियोजना से 20.26 हेक्टेयर क्षेत्र के 72 लाभार्थी किसानों की भूमि को सिंचित किया जाएगा। इस दौरान निर्माण अभियंता, अंकुश शर्मा, कनिष्ट अभियंता शशि पाल शर्मा, कृषक विकास संगठन कोलनी के प्रधान श्रीबेसर सिंह,उपप्रधान श्री हुकम चंद, उपप्रधानग्राम पंचायतभरनालश्रीजय सिंह, श्रीदुर्गा दास (किसान)व ठेकेदार श्री शोभा राम मौजूद रहे।

बहाव सिंचाई योजना कंसा खड्ड से गनेहर रोपा किसानों को सौंपी

मण्डी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करने के लिए खण्ड परियोजना प्रबंधक मण्डी द्वारा बहाव सिंचाई योजना कंसा खड से गनेहर रोपा का कार्य निर्माण पूर्ण होने पर यह परियोजना दिनांक 18.02.2025 को सम्बंधित कृषक विकास समूह को हस्तांतरित की गई। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 902 मीटर लम्बी मुख्य कूहल के साथ-साथ सिंचाई के लिए 2227 मीटर एचडीपीई जल वितरण पाइपों का भी उपयोग किया गया। इसके अलावा संप वैल, पम्प हाऊस और एमडीटी का भी निर्माण करवाया गया। इस परियोजना में 12.52 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई तथा इससे 57 किसान परिवार लाभांवित होंगे। इस उप परियोजना के निर्माण हेतु 34.10 लाख खर्च किए गए। हस्तांतरण के दौरान कृषक विकास समूह के प्रधान देवी राम प्रबंधक समिति के सदस्य तथा अन्य लाभार्थी उपस्थित थे। जिला परियोजना प्रबंधक, मण्डी डॉ. हेमराज वर्मा ने कूहल के रख-रखाव के बारे में जानकारी दी तथा किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कृषि संम्बधित उन्नत तकनीकों के बारे में और केवीए समूह को सुदृढ़ करने व इसका सुचारू रूप से संचालन एवं रख-रखाव पर कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस मौके पर परियोजना से सबंधित सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 (जायका ओडीए) के स्वामित्व में परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना भवन, कृषि परिसर, हमीरपुर-177001 से संपादित, प्रकाशित एवं मुद्रित।
फोन: 01972-223059. ई-मेल : iechpjicaagriculture9@gmail.com